



Mon - 12 Oct- 2026	Year - 01	Issue 201	Page - 01	Rs. - 5	www.azadvaani.com
--------------------	-----------	-----------	-----------	---------	-------------------

माई भागो ए.एफ.पी.आई. की 17 महिला कैडेटों ने एनडीए परीक्षा पास कर रचा इतिहास



चंडीगढ़, 12 अक्टूबर 2026। मोहाली स्थित माई भागो आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट (ए.एफ.पी.आई.) की 17 महिला कैडेटों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के अनुसार, यह देश के किसी भी सरकारी संस्थान, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सहित, से परीक्षा पास करने वाली महिला कैडेटों की सबसे बड़ी संख्या है।

पंजाब के रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने इस उपलब्धि पर कैडेटों, उनके परिवारों और प्रशिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता लड़कियों को सशस्त्र बलों में करियर बनाने के लिए तैयार करने की दिशा में पंजाब सरकार के प्रयासों को दर्शाती है। उन्होंने विश्वास जताया कि कैडेट आगामी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) प्रक्रिया में भी सफलता हासिल करेंगी।

मोहिंदर भगत ने माउंट व्यू इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक समारोह में की विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना



चंडीगढ़, 12 अक्टूबर 2026। पंजाब के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने डेराबस्सी स्थित माउंट व्यू इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के हुनर, आत्मविश्वास और रचनात्मकता की सराहना करते हुए उन्हें बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया।

मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कारों और सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि वे देश की प्रगति में योगदान देने वाले जिम्मेदार नागरिक बन सकें। उन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए स्कूल प्रबंधन के प्रयासों की प्रशंसा की। 'तरंग: वेक्स ऑफ टैलेंट' विषय पर आयोजित समारोह में संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया।

बंदी सिंहों की रिहाई के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाएगी पंजाब सरकार: भगवंत मान



चंडीगढ़, 12 अक्टूबर 2026। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य सरकार बंदी सिंहों की रिहाई के लिए सभी संभावित कानूनी और संवैधानिक रास्ते अपनाएगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित इस मामले का समाधान अनिश्चितकाल तक नहीं टाला जा सकता और इसमें न्याय, मानवता तथा संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों को ध्यान में रखना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने यह बात कौमी ईसाफ मोर्चा, सिख संगठनों, किसान यूनियनों और अन्य समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस मामले में सहयोग करने के लिए तैयार है और कानूनी प्रक्रिया के तहत समाधान निकालने में कोई बाधा नहीं बनेगी।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार और पंजाब के राज्यपाल को पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि यदि जगतार सिंह हवारा को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल दी जाती है, तो राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी निभाई

जाएगी। इसके बावजूद केंद्र सरकार की ओर से अभी तक पैरोल को मंजूरी नहीं मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी आश्वासन दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हवारा को कुछ दिनों की पैरोल मिलने से पंजाब में शांति और भाईचारे का सकारात्मक संदेश जा सकता है। उनके अनुसार, इससे अन्य बंदी सिंहों की रिहाई से जुड़े मामलों के समाधान की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने बुडेल जेल में बंद परमजीत सिंह भिओरा और जगतार सिंह तारा की पैरोल का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि यह मामला चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है और वह इसे पंजाब के राज्यपाल के समक्ष उठाएंगे, जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं।

बैठक में मौजूद पंजाब के महाधिवक्ता मनिंदरजीत सिंह बेदी को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित मामलों के कानूनी पहलुओं की जांच करें, ताकि उचित समाधान तलाशा जा सके। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार

संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए इन मामलों पर गंभीरता से काम करेगी।

उन्होंने सिख संगठनों से अपील की कि वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष शांतिपूर्ण तरीके से और कानून के दायरे में रहकर जारी रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ तत्व आंदोलनों को भटकाने और वैश्विक स्तर पर सिख समुदाय की छवि प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए शांति और भाईचारा बनाए रखना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार न्याय दिलाने के लिए जरूरी कानूनी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी और इस मुद्दे का संवेदनशीलता तथा जिम्मेदारी के साथ समाधान निकालने का प्रयास जारी रखेगी।

बैठक में मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, महाधिवक्ता मनिंदरजीत सिंह बेदी, गृह मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक शेखर, विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) पी.के. सिन्हा, जेल विभाग की प्रमुख सचिव भावना गर्ग, मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव कुमार अमित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

युवराज सिंह संभालेंगे पंजाब में कैंसर जागरूकता की कमान, पटियाला में 20 हजार लोगों की होगी स्क्रीनिंग

चंडीगढ़, 12 अक्टूबर 2026। पंजाब सरकार ने कैंसर की समय रहते पहचान और रोकथाम के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा स्थापित 'यू.बुई.कैन. फाउंडेशन' के साथ पटियाला जिले में कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान चलाने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत 12 महीनों में 20,000 लोगों की जांच करने का लक्ष्य रखा गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा एवं शोध मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉ. हितेंद्र कौर और फाउंडेशन की ट्रस्टी पूनम नंदा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कैंसर की शुरुआती अवस्था में पहचान करना और लोगों को नियमित जांच के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह युवराज सिंह ने क्रिकेट में देश का नाम रोशन किया और कैंसर से जंग जीती, उसी तरह अब वह कैंसर के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। समय पर बीमारी का पता चलने से उपचार अधिक प्रभावी हो सकता है।

अभियान के तहत 10,000 महिलाओं की स्तन कैंसर के लिए आधुनिक 'आई-ब्रेस्ट एग्जाम' उपकरण से जांच की जाएगी। यह गैर-आक्रामक और रेडिएशन-मुक्त तकनीक है। इसके अलावा 10,000 पुरुषों और महिलाओं की मुंह के कैंसर के लिए क्लिनिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। संदिग्ध लक्षण मिलने पर मरीजों को आगे की जांच और उपचार के लिए विशेषज्ञ स्वास्थ्य केंद्रों में भेजने की व्यवस्था भी होगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जांच को आसान बनाना और कैंसर स्क्रीनिंग को लेकर लोगों की झिझक दूर करना है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कैंसर का उपचार मुफ्त और केशलेस उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

डॉ. बलबीर सिंह ने यू.बुई.कैन. फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए बताया कि इसकी 'स्वस्थ महिला, स्वस्थ भारत' पहल के तहत देशभर में लगभग दो लाख महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिनमें पंजाब के मोगा जिले की करीब 14,000 महिलाएं शामिल थीं।

सरकार को उम्मीद है कि पटियाला में यह अभियान कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने, समय पर जांच को

प्रोत्साहित करने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करने में मदद करेगा।

इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से लोगों को कैंसर के शुरुआती लक्षणों, नियमित जांच और समय पर उपचार के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से उन लोगों तक स्क्रीनिंग सुविधाएं पहुंचाना है, जो जागरूकता की कमी या झिझक के कारण समय पर स्वास्थ्य जांच नहीं करवाते। विभाग और फाउंडेशन मिलकर लोगों को जांच के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि संदिग्ध मामलों की पहचान कर उन्हें आगे के उपचार से जोड़ा जा सके।



संगरूर को स्केटिंग हब बना रही पंजाब सरकार, खेल बजट बढ़ाकर 1,790 करोड़ रुपये किया: भगवंत मान



संगरूर, 12 अक्टूबर 2026। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार संगरूर को स्केटिंग हब के रूप में विकसित कर रही है, ताकि यहां के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल सकें। उन्होंने संगरूर पुलिस लाईंस में स्केटिंग खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान कहा कि सरकार खेल सुविधाओं को मजबूत करने और युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि संगरूर जिले के खिलाड़ी हर साल 70 से 80 राष्ट्रीय पदक जीतकर पंजाब का नाम रोशन कर रहे हैं। जिले में पहले दो स्केटिंग ट्रैक थे, जबकि अब धुरी में एक और विश्वस्तरीय स्केटिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। उन्होंने 19वीं और 20वीं एशियाई रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके माता-पिता और कोचों के योगदान की सराहना की।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि स्केटिंग एक चुनौतीपूर्ण खेल है, जिसमें तकनीक, कौशल, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सफलता के रास्ते में संसाधनों की कमी को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान खेलों को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिली, जबकि मौजूदा सरकार ने खेल क्षेत्र के लिए 1,790 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट रखा है। उन्होंने बताया कि 'खेड़ा वतन पंजाब दिया' के चौथे संस्करण के माध्यम से युवा प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल रहा है। इसके साथ ही राज्य में 3,000 से अधिक ग्रामीण खेल मैदान विकसित करने और गांवों में जिम स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

पंजाब की खेल विरासत का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबी खिलाड़ियों ने देश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल टीमों में पंजाबी खिलाड़ियों के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है।

SquareNet
Innovation & Excellence

Advertisement

Zoho Mail

Google Workspace

Microsoft 365

Microsoft Solutions Partner

Google Cloud Partner

aws partner network

Are you looking for a reliable EMAIL SERVICE PROVIDER?

Choose the best suitable plan for your business from **SquareNet**

Secure & Reliable

Professional Email

Cloud Integration

24/7 Expert Support

Scalable for Every Business

Empower Your Business with Secure, Professional & Scalable Email Solutions

SQUARENET INDIA PRIVATE LIMITED
C-6, Sebiz Square, IT Park, Sector 67,
Mohali 160062, Punjab India

www.squarenetindia.com

mail@squarenetsolutions.com

+91-904-101-2541
[PRI LINE]

Visit Us: www.azadvaani.com

For Enquiry Call: **+91-90414-88440**

HAFED कर्मचारियों की मांगों पर 15 अक्टूबर को अहम बैठक, समाधान नहीं निकला तो आंदोलन तेज करेगी यूनियन



बहुजन समाज को राजनीतिक आवाज देने के लिए ‘बहुजन एकता मोर्चा (अंबेडकरवादी)’ लॉन्च, एकजुटता पर जोर



पंचकूला। हरियाणा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी एम्प्लॉइज यूनियन ने सहकारी विपणन समितियों (CMS) और उनके कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। यूनियन ने इस संबंध में HAFED प्रबंधन को मांग-पत्र सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग उठाई थी। इसी कड़ी में 1 अक्टूबर को आयोजित बैठक में HAFED के एमडी चंद्रशेखर खेरा ने कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया था।

बैठक में तय किया गया कि 15 अक्टूबर को दोबारा बैठक होगी, जिसमें HAFED के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी शामिल होंगे। यूनियन को उम्मीद है कि इस बैठक में लंबित मांगों पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, यूनियन ने स्पष्ट किया है कि यदि मांगों का संतोषजनक समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए यूनियन ने हरियाणा सरकार और HAFED प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराने की बात कही है।

यूनियन की प्रमुख मांग धान खरीद पर मिलने वाले सर्विस चार्ज को मौजूदा 1.33 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का 0.25 प्रतिशत, यानी लगभग 5.97 रुपये प्रति क्विंटल करने की है। यूनियन का कहना है कि कम कमीशन के कारण समितियों की आय प्रभावित हो रही है और कर्मचारियों के वेतन सहित जरूरी खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है।

इसके अलावा, गेहूं खरीद पर वर्ष 2011 से 1.33 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिल रहे कमीशन में बढ़ोतरी की मांग की गई है। यूनियन के अनुसार, पिछले वर्षों में वेतन, श्रम और प्रशासनिक खर्च बढ़ने के बावजूद कमीशन में बदलाव नहीं हुआ है।

यूनियन ने मिड-डे मील योजना और आंगनबाड़ी केंद्रों तक गेहूं तथा चावल पहुंचाने के लिए मिलने वाले परिवहन शुल्क को बढ़ाकर कम से कम 150 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग भी उठाई है। इसके साथ ही गेहूं बीज पर सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी का भुगतान समय पर करने की मांग की गई है, ताकि समितियों पर आर्थिक बोझ न पड़े।

कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2024 से अनुमोदित संशोधित वेतनमान को जल्द लागू करने की मांग भी प्रमुख मुद्दों में शामिल है। यूनियन चाहती है कि ऑनलाइन खरीद-बिक्री के बढ़ते काम को देखते हुए समितियों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पद सृजित किए जाएं और डीसी रेट पर कार्यरत कर्मचारियों को रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए।

यूनियन ने खाद की बिक्री पर मिलने वाले मार्जिन में बढ़ोतरी की मांग करते हुए कहा कि खाद निर्माता कंपनियां 25 रुपये प्रति बैग तक मार्जिन देती हैं, जबकि HAFED की ओर से समितियों को 10 रुपये प्रति बैग दिए जाते हैं। यूनियन इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 20 रुपये प्रति बैग करने की मांग कर रही है।

यूनियन का कहना है कि इन मांगों का सीधा संबंध सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति, कर्मचारियों के वेतन और कार्यप्रणाली से है। ऐसे में प्रबंधन को जल्द सकारात्मक फैसला लेना चाहिए।

फिलहाल, 15 अक्टूबर को होने वाली बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकलता, तो यूनियन आंदोलन तेज करने की तैयारी करेगी। इससे सहकारी विपणन समितियों के कामकाज पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है।

यूनियन का कहना है कि सहकारी विपणन समितियां किसानों से जुड़ी खरीद प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। धान और गेहूं की

खरीद से लेकर खाद, बीज तथा अन्य कृषि संबंधी सेवाओं तक समितियों के कर्मचारियों पर कई जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे में कर्मचारियों को पर्याप्त संसाधन और उचित आर्थिक लाभ मिलना आवश्यक है, ताकि कामकाज सुचारू रूप से जारी रह सके।

यूनियन के प्रतिनिधियों के अनुसार, खरीद सीजन के दौरान कर्मचारियों पर काम का दबाव काफी बढ़ जाता है। किसानों की फसल की खरीद, रिकॉर्ड तैयार करने, भुगतान संबंधी प्रक्रियाओं और अन्य प्रशासनिक कार्यों को समय पर पूरा करना पड़ता है। उनका कहना है कि बढ़ती जिम्मेदारियों के अनुरूप कमीशन और संसाधनों में सुधार किया जाना चाहिए।

धान और गेहूं की खरीद पर मिलने वाले कमीशन का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समितियों के नियमित खर्चों का बड़ा हिस्सा इन्हीं गतिविधियों से जुड़ा है। यूनियन का तर्क है कि यदि कमीशन की दरों में समय के अनुसार संशोधन नहीं किया जाता, तो समितियों के लिए कर्मचारियों के वेतन और दूसरे जरूरी खर्चों का प्रबंधन करना कठिन हो सकता है।

परिवहन शुल्क बढ़ाने की मांग को लेकर यूनियन का कहना है कि मिड-डे मील योजना और आंगनबाड़ी केंद्रों तक खाद्यान्न पहुंचाने में समितियों को अपनी व्यवस्थाओं का उपयोग करना पड़ता है। परिवहन से जुड़े खर्चों में वृद्धि को देखते हुए मौजूदा शुल्क की समीक्षा जरूरी है। यूनियन चाहती है कि इस संबंध में ऐसा निर्णय लिया जाए, जिससे समितियों को होने वाले खर्चों की भरपाई हो सके। संशोधित वेतनमान का मुद्दा भी कर्मचारियों के लिए अहम बना हुआ है। यूनियन की मांग है कि 1 जनवरी 2024 से अनुमोदित वेतनमान को जल्द लागू कर कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाए।

वार्ड नंबर 3 की समस्याओं को लेकर निवासियों के बीच पहुंचीं अनु, कांग्रेस टिकट से पेश की दावेदारी

चंडीगढ़। दिसंबर महीने में प्रस्तावित चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों ने अपने-अपने वार्डों में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ने की इच्छुक अनु भी लोगों के बीच पहुंच रही हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। अनु लगातार वार्डवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रही हैं और क्षेत्र के विकास को लेकर अपना पक्ष रख रही हैं।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनु ने कहा कि वह इसी वार्ड की बेटी हैं और उन्होंने अपने जीवन का काफी लंबा समय यहीं बिताया है। इस कारण वह वार्ड की परिस्थितियों, स्थानीय लोगों की जरूरतों और उन्हें रोजाना पेश आने वाली समस्याओं से भली-भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि वार्डवासियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना और उनकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी।

वार्ड की समस्याओं का जिक्र करते हुए अनु ने आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 3 में पिछले दस वर्षों से भाजपा के पार्षद होने के बावजूद क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। उनके अनुसार, वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय निवासी मौजूदा व्यवस्था से निराश हैं और क्षेत्र में विकास कार्यों की जरूरत महसूस कर रहे हैं।

अनु ने कहा कि वार्ड के कई इलाकों में टूटी सड़कों, सफाई व्यवस्था की कमी, सीवरेज ब्लॉकिज और खराब स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। इसके अलावा पार्कों के उचित रखरखाव और अन्य नागरिक सुविधाओं को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का समाधान योजनाबद्ध तरीके से काम करने और संबंधित विभागों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने से ही संभव होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ने का उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल करना नहीं है, बल्कि वार्डवासियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाना और उनके समाधान के लिए प्रयास करना है। अनु के अनुसार, वह वार्ड के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर लोगों से सीधे संवाद करेंगी, उनकी शिकायतें और सुझाव सुनेंगी तथा स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास की कार्ययोजना तैयार करने का प्रयास करेंगी।

वार्ड के विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं के बारे में अनु ने कहा कि कॉलोनी में पर्याप्त सुविधाओं वाला एक बेहतर सामुदायिक केंद्र उपलब्ध करवाना उनका सपना है। मौजूदा सामुदायिक केंद्र छोटा होने के कारण लोगों को समारोह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए बड़े और सुविधाजनक सामुदायिक केंद्र की जरूरत है।

उन्होंने कॉलोनी में व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनके मुताबिक, वाहनों की पार्किंग को लेकर लोगों को होने वाली परेशानी दूर करने के लिए उचित प्रबंध किए जाने चाहिए। इसके साथ ही पार्कों का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करना भी उनकी प्रारथमिकताओं में शामिल है, ताकि निवासी स्वच्छ और सुविधाजनक सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सकें।

अनु ने कहा कि कॉलोनी में डिस्पेंसरी की सुविधा उपलब्ध करवाना भी जरूरी है। फिलहाल स्थानीय निवासियों को डिस्पेंसरी संबंधी सेवाओं के लिए ग्रेन मार्केट जाना पड़ता है, जिससे उन्हें असुविधा होती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होने से लोगों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा कॉलोनी में बेहतर सफाई व्यवस्था, नियमित कूड़ा उठाने और उचित कूड़ा प्रबंधन के लिए भी प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।

अनु ने वार्डवासियों से अपील की कि वे क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपने सुझाव और सहयोग दें। उन्होंने कहा कि किसी भी वार्ड का समग्र विकास जनता की भागीदारी और स्थानीय जरूरतों को समझकर ही किया जा सकता है। आने वाले दिनों में वह वार्ड के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क अभियान तेज करेंगी और लोगों से संवाद के माध्यम से उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगी।

अनु ने वार्डवासियों से अपील की कि वे क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपने सुझाव और सहयोग दें। उन्होंने कहा कि किसी भी वार्ड का समग्र विकास जनता की भागीदारी और स्थानीय जरूरतों को समझकर ही किया जा सकता है। आने वाले दिनों में वह वार्ड के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क अभियान तेज करेंगी और लोगों से संवाद के माध्यम से उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगी।

उन्होंने कहा कि सड़कें, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और सफाई जैसी सुविधाएं किसी भी क्षेत्र की बुनियादी जरूरतें हैं। इन व्यवस्थाओं का

सही होना लोगों के दैनिक जीवन को आसान बनाता है। इसलिए वार्ड में ऐसी समस्याओं की पहचान कर उन्हें संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाना और समाधान के लिए लगातार प्रयास करना आवश्यक है।

अनु के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई और उचित रखरखाव से कॉलोनी का वातावरण बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कूड़े का नियमित उठान, निर्धारित स्थानों पर कूड़ा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था की निगरानी जैसे कदमों पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रशासन के साथ-साथ नागरिकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने पार्कों को वार्ड के लोगों के लिए उपयोगी और आकर्षक बनाने पर भी जोर दिया। अनु ने कहा कि पार्क बच्चों, बुजुर्गों और परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान होते हैं। यहां बैठने की उचित व्यवस्था, हरियाली और नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि लोग अपने खाली समय में इन सुविधाओं का बेहतर उपयोग कर सकें।

अनु ने कहा कि कॉलोनी में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए उपलब्ध स्थान और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना बनाने की आवश्यकता है। अनियोजित पार्किंग से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस विषय को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित मंचों पर उठाया जाना चाहिए, ताकि निवासियों को राहत मिल सके।

स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर डिस्पेंसरी की उपलब्धता लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर जाने की जरूरत कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि कॉलोनी में इस सुविधा की आवश्यकता को संबंधित विभागों के समक्ष उठाने का प्रयास किया जाएगा।

सामुदायिक केंद्र को लेकर अनु ने कहा कि ऐसे केंद्र सामाजिक मेल-मिलाप और सामूहिक कार्यक्रमों के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। यदि केंद्र में पर्याप्त जगह और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों, तो स्थानीय निवासियों को पारिवारिक समारोहों तथा सामाजिक गतिविधियों के आयोजन में सुविधा मिल सकती है। उन्होंने इस दिशा में बेहतर व्यवस्था की जरूरत पर बल दिया।

बहुजन एकता मोर्चा ने संविधान की भावना और उसके मूल ढांचे की रक्षा को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया। मोर्चे ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी जांच एजेंसियों के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र कामकाज की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर नियुक्तियों की वकालत की।

मोर्चे ने स्वतंत्र एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया और वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक बताया। उसके अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम नागरिकों की भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है।

मोर्चे ने मानवाधिकारों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, शांतिपूर्ण आंदोलन के अधिकार, सभी के लिए किफायती आवास और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने की बात कही। इसमें स्वच्छ हवा, पीने योग्य पानी और गुणवत्तापूर्ण भोजन को भी प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा पुलिस व्यवस्था में सुधार और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

अंत में मोर्चे ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर युवाओं से इस पहल में शामिल होने की अपील की। प्रतिनिधियों ने कहा कि उनका उद्देश्य अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, जवाबदेह और पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए काम करना है। मोर्चे ने लोगों से संसद और विधानसभाओं तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए एकजुट होकर आगे आने का आह्वान किया।

मोर्चे के प्रतिनिधियों ने कहा कि बहुजन समाज की एकजुटता केवल राजनीतिक उद्देश्य तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे सामाजिक और आर्थिक बदलाव का आधार भी बनाया जाना चाहिए। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आपसी सहयोग, जागरूकता और समान अवसरों को बढ़ावा देकर ही एक मजबूत और समावेशी व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वंचित और पिछड़े वर्गों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाना समाज की जरूरत है। मोर्चे ने यह भी जोर दिया कि युवाओं को राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आगे आना चाहिए।



herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.



PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015